

गुरु एक्सप्रेस की प्रिंटिंग यूनिट पर रात्रि के समय 11 से 3 बजे तक काम करने वाले युवक (हेल्पर) की आवश्यकता है। वेतन योग्यता अनुसार है। वेतन योग्यता अनुसार है।

संपर्क

संपर्क समय - शाम 4 से 6 बजे तक

कार्यालय दैनिक गुरु एक्सप्रेस

9425105928, 8319964648

गुरु एक्सप्रेस

सुबह का अखबार

संपादक - आशुतोष नवाल

वर्ष 18

अंक 152

पृष्ठ 4

मन्दसौर

गुरुवार 14 मार्च 2024

मूल्य 2 रुपया



जल्द लग सकती है आमचुनाव की आचार संहिता

केन्द्रीय केबिनेट की अंतिम

बैठक भी संपन्न

मन्दसौर, 13 मार्च गुरु एक्सप्रेस

देश के आम चुनाव को लेकर अधिकारी

अपने काम में लगे हुए हैं। लोकसभा

चुनाव 2024 के कार्यक्रमों की घोषणा

पर सभी की नजर टिकी है। बताया जा रहा है कि अगले दो-तीन दिनों में चुनाव

आयोग लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम

जारी कर सकता है। इसी के साथ अंतिम

संहिता भी लग जाएगी। बात है कि देश

के दो सह निर्वाचन आयुकों की घोषणा

होना है। माना जा रहा है कि यह नियुक्ति

होते ही निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम

जारी कर देगा। इधर केंद्रीय केबिनेट की

अंतिम बैठक भी हो गई है। मतलब सकार

ने अपने सारे कार्य पूर्ण कर लिए हैं।

चुनाव कार्यक्रम की संभावित

घोषणा को देखते ही सभी अधिकारियों-

कर्मचारियों को हड्डियार्टर पर ही रहने

के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेशभर में

निर्वाचन काम में लगे अधिकारियों-

कर्मचारियों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं।

राज्य के सभी जिलों में जिला निर्वाचन

अधिकारीयां नियमित करकर्ट ने इस संबंध

में आदेश जारी कर अवधारणा पर पूर्ण

प्रतिबंध लगा दिया है। अब अधिकारियों-

कर्मचारियों को मुश्किलों पर ही रहना

होगा और कोई भी बिना अनुमति के छुट्टी

पर नहीं जा सकेगा। नियर्वाचन अधिकारी

का यह आदेश तकाल प्रभाव से लगा

कर दिया गया है। आदेश के अनुसार

लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संप्रांत होने

तक यह आयोगी रहेगा। आदेश जारी होने

में यह जिलासारी भी है कि इस बार

लोकसभा चुनाव कितने बरणों में होगा।

पिछली बार यानि वर्ष 2019 में

लोकसभा चुनाव 7 बरणों में कराए गए

था। तब चुनाव की घोषणा 10 मार्च को

की गई थी और देशभर में 11 अप्रैल से

19 मई की बीच मतदान कराया गया था।

योग्यपुर, खंडवा और बालाघाट

उपलब्धता की स्थिति को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन मांगते हैं।

मध्य प्रदेश में 64 हजार 523

मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक केंद्र पर चार

अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टी लगती

है। इस प्रकार 2 लाख 58 हजार 92

कर्मचारी लाते हैं। इसके साथ नियर्वाचन

प्रदेश की मुख्य नियर्वाचन पदाधिकारी

कर्मचारियों की छुट्टी लगती है।

योग्यपुर, खंडवा और बालाघाट

की आवश्यकता है। लेकिन, जिलों में

नियर्वाचन कर्मचारियों की कमी है। योग्यपुर,

खंडवा और बालाघाट में मुख्य नियर्वाचन

पदाधिकारी कार्यालय से संविदा

कर्मचारियों की छुट्टी मतदान दल सहित

अन्य कार्यों में लगानी की अनुमति मांगी

है। मुख्य नियर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय

ने कलेक्टर से कर्मचारियों की

मानव अधिकार आयोग ने जवाबदारों

से जवाब मांगा है।

मानव अधिकार आयोग ने

जवाबदारों से मांगा जवाब

मन्दसौर, 13 मार्च गुरु एक्सप्रेस

मंगलवार को भानपुर थाना क्षेत्र में कुरुक्षेत्र

के हमले से हुई बच्ची की मौत के मामले में मानव अधिकार आयोग ने जवाबदारों

से जवाब मांगा है।

दरअसल भानपुर नगर के पास आवारा कुरुक्षेत्र

के ऊपर जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई थी। लोटखेडी निवासी

बालिका अकेले ही अपने खेत से घर की तरफ जा रही थी, तभी अचानक

आवारा कुरुक्षेत्र के झुंझुने ने उस पर हमला कर दिया था। जिससे बालिका गंभीर

रुप से घायल हो गई। कुरुक्षेत्र को आवारा सुनने के बाद परिजन व अन्य खेत

वाले पड़ोसी जब भीकर पर हुए तो बालिका लहूलहाना हालत में पूरी

परिजन बालिका को अस्पताल ले कर पहुंचे, लेकिन किसको नहीं

मानव अधिकार आयोग ने उसे रक्त

घोषित कर दिया था। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार

आयोग ने कलेक्टर, मन्दसौर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, भानपुर-

मन्दसौर से मामले की जांच कराकर बालिका की मुख्य के सम्बन्ध में स्पष्ट

प्रतिवेदन तथा मृतक का परिजन को लेकर 13

प्रदेश में लंबे समय से रिक्त पदों के

विरुद्ध भर्तीयां नहीं हुई हैं। तक्तालीन

शिवराज सरकार ने विधानसभा

चुनाव के दूसरे दिन एक लंबे रुप से

रिक्त पदों के लिए प्रत्येक दो दिनों

में एक दिन एक दिन एक दिन

में एक दिन ए



सेवा, समर्पण और सर्वस्पर्शी विकास के



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री



दिन



■ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी प्रतिबद्धता घोषणाओं और शिलान्यासों तक सीमित नहीं हैं, हम विकास को धरातल पर उतारने में विश्वास रखते हैं और इसी के लिए निरंतर कार्यरत हैं। वर्ष 2047 तक देश और मध्यप्रदेश को विकसित बनाने के लिए हम तेज गति से दौड़ रहे हैं। एयरपोर्ट, हाई-वे और रेलवे जैसी अधोसंरचना के साथ-साथ पढ़ाई, पानी और पर्यावरण से जुड़े कार्यों को भी नई गति मिली है। देश में तेजी से हो रहे नगरीकरण के अनुकूल आधुनिक अधोसंरचना का विस्तार किया जा रहा है, यही डबल इंजन सरकार का मूल मंत्र है। ■

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

**आध्यात्मिक अभ्युदय ▶▶▶**

- श्रीराम-वन-गमन पथ विकास के लिये न्यास की पहली बैठक का आयोजन
- भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े स्थानों को धार्मिक स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना
- प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में चित्रकूट के घाट पर अध्यात्म का अनुभव परियोजना का भूमिपूजन
- गौरवशाली संस्कृति एवं ऐतिहासिक विरासत पर केन्द्रित विक्रमोत्सव 2024 का उज्जैन में आयोजन
- प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्जैन में विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ
- देवस्थानों के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिये मंत्रीगणों की समिति का गठन
- सिंहस्थ महाकुंभ-2028 के कार्यों के लिये 19 विभागों की ₹19 हजार करोड़ की प्रारंभिक कार्ययोजना
- इंदौर से उज्जैन, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जबलपुर से चित्रकूट तथा ग्वालियर से ओरछा एवं पीताम्बरा पीठ के लिये हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ करने का निर्णय
- श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये अयोध्या में आस्था भवन (धर्मशाला) निर्माण का निर्णय
- शासकीय कैलेंडर में विक्रम संवत् अंकित किये जाने का निर्णय
- देवालयों में लगाने वाली सामग्री के निर्माण को कुटीर उद्योग के अंतर्गत प्रोत्साहन देते हुए स्व-सहायता समूहों और युवाओं को प्रशिक्षण एवं मंदिरों में सामग्री के स्टॉल लगाए जाने का निर्णय

गौ-संरक्षण एवं संवर्धन ▶▶▶

- भारतीय नव वर्ष अर्थात् इस चैत्र माह से अगले वर्ष तक गौ-वंश रक्षा वर्ष मनाने का निर्णय
- गौशालाओं को प्रति गौ-वंश मिलने वाले ₹ 20 की राशि बढ़ाकर ₹ 40 करने का निर्णय
- चरनोड़ी की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाएंगे

90 उपलब्धियां

- गौशालाओं को भूमा प्रबंधन के लिये आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों के लिये अनुदान तथा प्रोत्साहन
- प्रत्येक 50 किलोमीटर पर घायल गायों को इलाज के लिये परिवहन हेतु हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहन का टोल व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंध का निर्णय
- अधूरी गौशालाओं का निर्माण पूर्ण कर नई गौशालाएं प्रारंभ करने का निर्णय
- गौशालाओं को श्रेष्ठ संचालन के लिये पुरस्कृत किया जाएगा

**किसान कल्याण ▶▶▶**

- गैंडा का समर्थन मूल्य ₹2275 के साथ ₹125 प्रति किंचंटल बोनस देने का निर्णय
- किसान सम्मान निधि में 80 लाख से अधिक किसानों को ₹1816 करोड़ की सहायता
- फसल बीमा योजना खरीफ (2023) में 25 लाख से अधिक किसानों को ₹755 करोड़ के दावों का भुगतान
- शृंखला प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को फसल ऋण की सुविधा

**महिला सशक्तिकरण ▶▶▶**

- 1.29 करोड़ लाडली बहनों को ₹4728 करोड़ की सहायता
- 46 लाख बहनों के खाते में ₹450 में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के लिए ₹118 करोड़ की राशि का अंतरण
- 2 लाख 45 हजार से अधिक लाडली लक्ष्मी बेटियों को ₹86 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति
- महिला स्व-सहायता समूहों को ₹9838 करोड़ की ऋण सहायता

**जनजातीय कल्याण ▶▶▶**

- प्रधानमंत्री जी द्वारा ₹170 करोड़ की लागत से खरगोन में क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का शिलान्यास
- तेंदूपता संग्राहकों का मानदेय ₹3000 प्रति बोरा से बढ़कर ₹4000 हुआ, लगभग 35 लाख तेंदूपता संग्राहकों को लाभ
- पीएम जन-मन योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल जिलों में ₹7300 करोड़ की लागत से हो रहे अधोसंरचना कार्य। 11 लाख से अधिक भाई-बहन लाभान्वित
- श्रीअन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को प्रति किंचंटल ₹1000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन
- पीएम जन-मन मिशन में बैगा, भारिया और सहरिया अविद्युतीकृत घरों में बिजली पहुंचाने के लिये एक किलोवॉट क्षमता की ऑफ प्रिड प्रणाली (सोलर+बैटरी) से बिजली पहुंचाने की योजना



अधोसंरचना विकास ▶▶▶

- ₹5000 करोड़ की लागत से उज्जैन-जावरा 4-लेन ग्रीनफिल्ड एक्सेस कंट्रोल हाई-वे निर्माण का निर्णय
- ₹10 हजार करोड़ से अधिक लागत की 724 कि.मी. लंबी 24 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास
- ₹350 करोड़ की लागत से इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमिपूजन। भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना में भी बन रहे हैं एलिवेटेड कॉरिडोर
- प्रधानमंत्री जी द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर एयरपोर्ट के नये टर्मिनल भवन का लोकार्पण। ₹24 हजार 500 करोड़ की अधोसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण
- 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास तथा 133 रेल ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास एवं लोकार्पण
- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं सागर में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा में 550 से अधिक शहरी ई-बसों के संचालन का निर्णय
- ₹1540 करोड़ की लागत से भोपाल मेट्रो के 8 नये स्टेशनों का भूमिपूजन
- कायाकल्प अभियान में ₹2500 करोड़ के निवेश से बदल रही है शहरी सड़कों की तस्वीर
- ₹308 करोड़ की लागत से खरगोन जिले में जलूद ऊर्जा संयंत्र का भूमिपूजन
- ग्वालियर-बैंगलुरु, ग्वालियर-अहमदाबाद और ग्वालियर-दिल्ली-अयोध्या विमान सेवा का शुभारंभ
- जबलपुर में ₹486 करोड़ की लागत से मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के लिये नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति



शिक्षा एवं युवा कल्याण ▶▶▶

- प्रत्येक जिले में एक शासकीय महाविद्यालय का पी.एम. उत्कृष्टता महाविद्यालय के रूप में उत्पन्न का निर्णय
- सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय एवं खरगोन में क्रान्तिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का शुभारंभ
- आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में देश के पहले शोध-आधारित नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता अनुभवात्मक विद्यार्थी केन्द्र का लोकार्पण
- शासकीय नौकरियों के लिये घरनित लगभग 10 हजार उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदाय
- प्रदेश के स्टार्ट-अप्स को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिये ₹50 हजार से लेकर ₹1.50 लाख तक वित्तीय सहायता का प्रावधान
- राज्य स्तरीय रोज़गार दिवस के अवसर पर 7 लाख युवाओं को ₹5 हजार करोड़ का स्व-रोज़गार ऋण वितरित
- शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को छठवें वेतनमान स्कीम के अनुरूप अकादमिक ग्रेड-पे दिए जाने का निर्णय
- विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की अंकसूची एवं उपाधियों को डिजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था
- आगर-मालवा में नया विधि महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय
- शिक्षा में गुणवत्ता के लिये भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, रीवा के 6 विश्वविद्यालयों में इन्वेस्टिशन केंद्रों की स्थापना
- उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में मध्यप्रदेश राष्ट्रीय औसत से अग्रणी
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्यप्रदेश
- व्यावसायिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा का एकीकरण कर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर 35 व्यावसायिक विषयों का पाठ्यक्रम में समावेश



जल प्रबंधन ▶▶▶

- ₹35000 करोड़ लागत की 3.37 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना स्वीकृति
- ₹4168 करोड़ की लागत से 1.20 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की सीतापुर-हनुमन माइक्रो सिंचाई परियोजना को स्वीकृति
- खरगोन जिले में ₹557 करोड़ से अधिक की पीपरी माइक्रो उद्धवन, बलकवाड़ा माइक्रो उद्धवन, चौण्डी जामुनिया माइक्रो उद्धवन सिंचाई परियोजनाएं तैयार
- शामगढ़-सुवासरा, मोहनपुरा तथा आगर-मालवा की कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजनाओं से 1.39 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विस्तार



स्वास्थ्य ▶▶▶

- पीएम श्री एयर एम्बुलेंस का शुभारंभ** गंभीर बीमार अथवा दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को एयरलिफ्ट से समय पर उपचार की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलेगा निःशुल्क लाभ
- निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में उपकरणों के लिये ₹1200 करोड़ की स्वीकृति
- प्रदेश में 13 नये नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय
- उज्जैन में नये शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण के लिये ₹592 करोड़ की स्वीकृति
- सभी जिला अस्पतालों में शर्व वाहन की व्यवस्था
- सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, धार, झाबुआ, मंडला, बालाघाट, श्योपुर एवं खजुराहो में नये आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय



उद्योग एवं निवेश ▶▶▶

- औद्योगिक विकास को तेज करने के उद्देश्य से उज्जैन में दो दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्वेलेव का सफल आयोजन
- कॉन्वेलेव में 283 डकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि का आवंटन। इन डकाइयों द्वारा ₹12 हजार 170 करोड़ से अधिक का निवेश। 20 हजार से अधिक लोगों को मिलेंगे रोज़गार के अवसर
- ₹10 हजार करोड़ से अधिक लागत की 61 से अधिक उद्योग डकाइयों का शुभारंभ, 17 हजार से अधिक रोज़गार सृजन की संभावना
- ₹1 लाख करोड़ से अधिक के मिले निवेश प्रस्ताव
- कॉन्वेलेव में कुल 12 देशों और 650 से अधिक औद्योगिक निवेशकों द्वारा भागीदारी। 4000 से अधिक डेलिगेट्स ने लिया भाग, 2100 से अधिक बिजेनेस-टू-बिजेनेस बैठकें
- प्रदेश के प्रमुख शहरों में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्वेलेव के आयोजन का निर्णय
- ग्वालियर व्यापार मेला की तर्ज पर उज्जयिनी विक्रम व्यापार मेला प्रारंभ। ₹2300 करोड़ के कारोबार का अनुमान

जनोन्मुखी प्रशासन ▶▶▶

- लाउड स्पीकर के अनियंत्रित एवं अनियमित प्रयोग पर प्रतिबंध
- प्रदेश में खुले में मांस-मछली की बीक्री प्रतिबंधित
- प्रशासनिक संवेदनहीनता तथा लापरवाही पर कठोर कार्यवाही
- जनहितेषी विषयों पर त्वरित निर्णय- बीआरटीएस हटाने का फैसला
- प्रधानमंत्री जी द्वारा सायबर तहसील परियोजना का सभी 55 ज़िलों में शुभारंभ
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संभागों की समीक्षा बैठकों का आयोजन, विकास एवं कानून व्यवस्था के विषयों पर चर्चा तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप त्वरित निर्णय
- प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण एवं युक्तियुक्तकरण के लिये प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग बनाने का निर्णय
- राजस्व महाअभियान के तहत 10 मार्च तक नामांतरण, बंटवारा, अमिलेख दुरुस्ती, सीमांकन आदि के 30 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा
- विकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय सुशासन और कार्यदक्षता का उदाहरण बना
- प्रदेश में बोरवेल के खुले गड्ढे अभियान चलाकर किये गये बंद
- 2 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को पात्रतानुसार उच्च पद का प्रभार
- मंत्रिपरिषद के सदस्यों के नेतृत्व क्षमता विकास पर लीडरशिप समिट बनी दूसरे राज्यों के लिये उदाहरण
- प्रत्येक जिले में जिला पुलिस बैंड का गठन



श्रमिक कल्याण ▶▶▶

- इंदौर की हुक्मचंद मिल के 4800 श्रमिक परिवारों को ₹224 करोड़ की राशि का भुगतान
- अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी ₹1,625 से ₹11,450, अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी ₹1,764 से ₹12,446, खेतीहर मजदूर की मजदूरी ₹1,396 से बढ़ाकर ₹9,160 करने का निर्णय
- श्रमिकों को ई-स्कूटर खरीदने पर आर्थिक मदद का फैसला
- संबल योजना के माध्यम से दिवंगत या विकलांगता के दौरान दी जाने वाली सहायता राशि ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख करने का फैसला



विविध ▶▶▶

- स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहर का लगातार सातवीं बार इंदौर को मिला पुरस्कार
- मध्यप्रदेश को देश का दूसरा स्वच्छतम् राज्य और भोपाल को मिला स्वच्छतम् राजधानी का पुरस्कार
- मध्यप्रदेश को देश में सर्वाधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी में मिला प्रथम स्थान
- भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा देशभर के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में देवास के सिविल लाइन थाने का चयन
- राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2022 और राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार 2023 के अंतर्गत मध्यप्रदेश "लीडर" के रूप में पुरस्कृत

